International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 04, April 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वर्तमान समय में भारत–चीन संबंध : उभरते मुद्दे और चुनौतियाँ

पवन कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी
Email - pawankagra90@gmail.com

शोधसार :

वर्तमान समय मेंजब विश्व व्यवस्था कोवैश्विक महामारी ब्वअपक.19 से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है। ऐसे समय में एशिया में विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं, हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी है,जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाएँ आमने–सामने आ गई है। भारत का आरोप है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना अवैध रूप से टेंट लगाकर सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर रही है,तो वहीं दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधि अवैध निर्माण कर रहा है। इस घटना से पूर्व भी उत्तरी सिक्किम केनाथूला सेक्टर में भारतीय व चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी। उपरोक्तघटनाएँ दोनों दशों के बीच रक्षा व सुरक्षा संबंधों की जटिलता को प्रदर्शित करती है। यह विदित है कि भारत और चीन दोनों देशों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई थी। भारत ने जहाँ सच्चे अर्थों म लोकतंत्र के मूल्यों को खुद में समाहित किया,तो वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया। भारत–चीन संबंधों की इस गाथा में सन 2021 तक अनेकों मोड आए हैं। हिंदी–चीनी भाई–भाई के नारे से लेकर वर्ष 1962 के भारत–चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध आज इस दौर में है कि भारत व चीन विभिन्न मंचों पर एक–दूसरे कीमुखालफत करते नजर आते हैं। अतः दोनों देशों के बीच संबंधों को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में भारत–चीन संबंधों की व्यापकता पर चर्चा करते हुए वर्तमान में दोनों देशों के बीच विवाद के बिंदुओंव सहयोग के क्षेत्र का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्य शब्द –मुखालफत,साम्राज्यवाद,पंचशील,संप्रभुता] LAC, NPT, CTBT, OBOR, CPEC, NSG, P5, DokM आदि।

शोध पद्धति :

प्रस्तुत शोध पत्र को पूरा करने के लिए अधिकांश सामग्री द्वितीय स्त्रोतों से प्राप्त की गई है व इसमें ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक विधि के साथ शोधकर्ता के निजि विचार भी शामिल किए गए हैं तथा इसके अलावा पुस्तकों सेसंकलितसामग्री समाचार पत्रोंव पत्रिकाओं से प्राप्त तथ्यों के आधार भारत–चीन संबंधों में मुख्य समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

शोध उद्देश्य :

1. भारत–चीन के मध्य विभिन्न मद्दों का अध्ययन करना।

2. COVID19] CPEC o OBOR के कारण भारत–चीन संबंधों आए नए आयामों का पता लगाना।

भूमिका :

आज भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध एक बार फिर नाजुक दौर में पहुँच गए हैं। इसका नकारात्मक असर यह हुआ है कि दशकों बाद जिस तरह से चीन के प्रति भारत के लोगों में विश्वास पनप रहा था,वह एक बार फिर से भंग हुआ है। पिछले कुछ महीनों में भारत को अपनी सीमाओं पर उतार–चढ़ाव वाले अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ा है। सन् 2020 के मई महीने की गर्मियों में भारत और चीन की सरहद वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर गरमा–गरमी ओर तनातनी का माहौल रहा। दोनों देशों की आर्मी के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के चलते 20 भारतीय जवान शहीद हो गए जबकि 40 चीनी सैनिकों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दुनिया की सबसे लंबी विवादित सरहद पर 1975 के बाद से यह अब तक का सबसे गंभीर सैनिक टकराव था।

यदि बात करें भारत–चीन संबंधों के विकास की तो हजारों वर्षों तक तिब्बत में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा, परंतु सन् 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ कब्जा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। बीसवीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थ यात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित है। वर्ष 1954 में नेहरू और चाऊ–एन–लाई ने ''हिंदी–चीनी भाई–भाई'' के नारे के साथ ''पंचशील सिद्धांत समझौता'' पर हस्ताक्षर किए,ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। लेकिन वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तथा उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इससे नाराज होकर चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के कारण संबंधों को गंभीर झटका लगा तथा उसके बाद वर्ष 1976 में भारत–चीन राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया। वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देश सीमा विवाद के प्रश्न पर पारंपरिक स्वीकार्य समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सहमत हुए। वर्ष 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन भारत की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया तथा दोनों पक्षों ने भारत–चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा कर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2011 को 'चीन–भारत विनियम' वर्ष तथा वर्ष 2012 को 'चीन–भारत मैत्री व सहयोग वर्ष' के रूप में मनाया गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए नाथूला दर्रा खोलने का फैसला किया तथा इसी वर्ष भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष मनाया। वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के बीच वुहान में 'भारत–चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उसके बीच गहन विचार–विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दो के साथ–साथ घरेलू एवं विदेश नीति से संबंधित दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति बनी। वर्ष 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच चेन्नई में 'दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

वर्ष 2020 में भारत–चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ है तथा भारत–चीन सांस्कृतिक तथा पीपल–ई–पीपल संपर्क का वर्ष भी है। उपरोक्त संधि समझौते तथा घटनाओं के बावजूद भी आज भारत–चीन संबंध कटुता के दौर में है, जिनको हम अनेकों विवादों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे।

भारत–चीन सीमा विवाद :

भारत और चीन के बीच पिछले कुछ महीनों से एल.ओ.सी. और एल.ए.सी. पर तनाव जारी है। चीन के कब्जे में लद्दाख का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तथा कराकोरम दर्रे के पश्चिम में 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाक ने चीन को दिया हुआ है। यही कारण है कि भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन तथा अरूनाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद जारी है। दोनों ही देश दोनों क्षेत्रों पर अपना–अपना दावा प्रस्तुत करते हैं,यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में अक्साई चिन,चीन के पास है,जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है। मई 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया था,तो उनका एक मुख्य उद्देश्य चीन के शीर्ष नेतृत्व को वास्तविक नियंत्रण रेखा के स्पष्टीकरण पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना भी था ताकि एल.ओ.सी. और एल.ए.सी. पर शान्ति व्यवस्थ स्थापित की जा सके।

दक्षिण चीन सागर का मुद्दा :

यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चीन, दक्षिण चीन सागर के 90 प्रतिशत हिस्से पर अपना अधिकार बताता है तथा चीनताइवान और वियतनाम स्प्राटल द्वीप समूह पर अपनी दावेदारी बताता रहता है। स्प्राटल द्वीप दक्षिण चीन सागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत वियतनाम के अनुरोध पर दक्षिण चीन सागर से तेल का अन्वेषण करता है और चीन हमेशा से भारत के इस कदम की आलोचना करता रहा है।

दक्षिण चीन सागर के अलावा भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर भी विवाद बना रहता है– पिछले कई वर्षों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बांध का निर्माण कर रहा है और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। यह भी दोनों देशों के मध्य विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है।

वन बेल्ट वन रोड (OBOR) और भारत :

वन बेल्ट वन रोड ;व्ठव्द्ध चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क योजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क रेल एवं जल मार्गों के माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका राज्यों से जोड़ना है। परंतु भारत अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की ;व्ठव्द्धपहल में चीन–पाक आर्थिक गलियारा ;ब्व्म्द्ध को भी शामिल किया गया है। क्योंकि ब्व्म् गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अतः व्ठव् में शामिल होने का मतलब है कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाक के अधिकार को सहमति प्रदान करना, जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। वास्तव में चीन द्वारा निर्मित परियोजना अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग बंदरगाहों के विकास,औद्योगिक केंद्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास करके तथा भारत के पड़ोसी राज्यों को भारत के खिलाफ भड़का कर स्वयं वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है,जो भविष्य में भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

धारा 370 और चीन :

1947 में भारत–पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर दोनों देशों के बीच विवादित मुद्दा रहा है। 1947 के बाद जम्मू भारत प्रशासित कश्मीर औरलद्दाख भारत के नियंत्रण में है, वहीं पाक प्रशासित कश्मीर और उत्तरी कश्मीर (गिलगित और बलिस्तान) पाकिस्तान के नियंत्रण में है जबकि अक्साई चीन और ट्रांस काराकोरम (शक्सगाम घाटी) चीन के पास है। 1948 तक शक्सगामघाटी पर पाक का नियंत्रण था लकिन 1965 में एक समझौते के द्वारा पाक ने यह क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। अतः भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से 370 हटाने के कारण चीन का कहना है कि इस विषय को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद केरेजोल्यूशन और द्विपक्षीय समझौते क आधार पर सुलझाया जाना चाहिए तथा चीन द्वारा यह भी कहा गया कि भारत ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। चीन की इस प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वह लद्दाख पर अपने दावे को दोहरा रहा है।

भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता पर चीन का रुख :

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह ;छैळद्ध की स्थापना 1975 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य राज्यों की संख्या 48 है। यह समूह परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री नियंत्रण रखता है। इस समय भारत में परमाणु संयंत्र लगाए जाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत सरकार स्पष्ट भी कर चुकी है कि उसका उद्देश्य बिजली तैयार करना है और छैळ की सदस्यता मिलने से उसकी राह आसानहो जाएगी। लेकिन छैळ की सदस्यता के लिए भारत ने कई शर्तों को मंजूर करना होगा जैसे –परमाणु अप्रसार संधि ;छच्ज्द्धए व्यापक परमाणु अप्रसार संधि ;ब्ज्ठज्द्ध आदि।अतः छच्ज पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के कारण चीन पाकिस्तान से मिलकर भारत की छैळ की सदस्यता का कड़ा विरोध करता है, जिसके कारण भारत व चीन के हितों में टकराव की स्थिति रहती है और साथ में चीन भारत का सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का भी विरोध करता रहता है।

क्वाड (क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग) के कारण चीन की बढ़ती चिंता :

वर्ष 2007 के बाद चीन ने एशिया–प्रशांत महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन अपने पड़ोसी राज्यों को भी धमकाने लगा तथा 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' की नीति के तहत समुद्र में सैन्य बेस लगातार बढ़ाने लगा। समुद्र में चीन की बढ़ती शक्ति को देखकर वर्ष 2017 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड की स्थापना की ताकि एशिया–प्रशांत महासागर में शांति व शक्ति

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 12, December 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

संतुलन बनाए रखा जा सके। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है और लगातार क्वाड़ देशों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहता रहता है। दरअसल चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी राजनीतिक साजिश को रच रहे हैं। क्योंकि क्वाड़ के सभी सदस्य देश (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) मालाबार सैन्य अभ्यास में भी भाग लेते हैं, जिस कारण चीन अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है तथा भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझता है।

कोविड–19 (Covid-19) के समय भारत–चीन मतभेद :

वैश्विक महामारी 'कोविड–19' जिसने समूचे विश्व को घुटनों पर ला दिया तथा विश्व की च5 महाशक्तियाँ (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस) आदि भी कोविड–19 के सामने कमजोर पाई गई। जिस कारण पूरे विश्व को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यह महामारी चीन की वुहान लैब से पूरे विश्व में फैली है। कुल मिलाकर इस वैश्विक संकट के लिए चीन को जिम्मेदार माना जाता है। इस कोविड–19 के कारण भारत ने भी वर्ष 2020 व 2021 में बहुत सारी दिक्कतों व परेशानियों का सामना किया। जिस कारण भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया व आदि देशों के साथ मिलकर चीन को वैश्विक व्यवस्था से अलग–थलग करने के लिए प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं वर्ष 2020 के कोविड–19 के समय भारत ने 'विश्व का दवाखाना' की अपनी छवि के अनुरूप भूमिका निभाने का प्रयास किया। भारत ने अपने पड़ोसी देशों व विश्व के अन्य देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरीन व पेरासिटामोल दवाओं का निर्यात किया, जो भारत की 'मेडिकल कूटनीति' को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने]ासकर दक्षिण एशिया के देशों (बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाक, श्रीलंका, मालदीव) आदि को अपने देश में निर्मित वैक्सीन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े उपकरण प्रदान करके भारत के पड़ोसी पहले की नीति को आघात पहुँचाया है, जिस कारण भारत–चीन संबंधों में कटुता बढ़ी है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारत–चीन संबंधों में उभरते हुए नए आयामों पर प्रकाश डालते हुए दोनों देशों पर पड़े प्रभाव का गहनता से अध्ययन किया गया है। यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से चीन अपनी 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स','चेक बुक डिप्लोमेसी','बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव' तथा 'शीत युद्ध 2.0' आदि के माध्यम से भारत को आर्थिक सुरक्षा व राजनीतिक आधार पर कमजोर करना चाहता है, ताकि दक्षिण एशिया में उसके समान महाशक्ति का उदय न हो। भारत व चीन एशिया की उभरती हुई सर्वोच्च शक्ति है। इन दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक संबंधों में टकराव है। चीन–पाक आर्थिक गलियारा ;ब्म्ब्द्ध के कारण तो भारत व चीन के व्यापारिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। चीन द्वारा भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए बार–बार विरोध किया जाना, भारत को भी रास नहीं आ रहा है। चीन व भारत के बीच मुख्य मुद्दा सीमा विवाद भी है, जिस कारण दोनों देशों के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होती रहती है। अतः इस सदी को एशियाई सदी के रूप में फलित करने के लिए दोनों देशों के लिए 'कांटेस्ट ऑफ द सुंचुरी' से नामित पारदर्शिता में सहयोग तथा विश्वास तत्वोंको सम्माहित करना होगा। भारत और चीन के बीच की समस्याओं को अल्पावधि में हल किया जाना कठिन है, लेकिन मौजूदा रणनीतिक अंतर को कम करके, मतभेदों को कम करके और यथास्थिति बनाए रखने जैसे उपायों से समय के साथ आपसी संबंधों को और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. इकोनामिक कॉरिडोर चाइनीस आफिशियल सेट्स रिकॉर्ड व एक्सप्रेस ट्रिब्यून,2 मार्च 2015
2. पंथ पष्पंश, अंतरराष्ट्रीय संबंध, एम.सी. ग्रै हिल एजुकेशनपब्लिकेशन, पृष्ठ 280
3. दृष्टि द विज़न, अक्टूबर 2017
4. दृष्टि द विजन, मई 2020
5. थरूर शशि,''डोकलाम, सीमा–स्थिति और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित चीन–भारत संबंधों पर रिपोर्ट'',4 सितंबर 2018
6. चाइनीस लैण्डमार्क इन्वेस्टमेंट इन पाक एक्सप्रेस ट्रिब्यून,21 अप्रैल 2015
7. कुमार संजय,''भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ'' एम.सी. ग्रै हिल पब्लिकेशन,2013,पृष्ठ 22–26
8. ओझा एन.एन,''अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाऐं'' क्रॉनिकलमैग्जीन,2017,पृष्ठ 97